सिंचाई मंत्री की स्वीकृति से उस पद पर नियुक्त किया गया था । उनका वेतन वित्त मंत्रालय के परामर्श से तय किया गया था और इस संबंध में किन्हीं भी नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है । संस्थान में उनका कार्यकाल (टर्म) अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

(ङ) इस संबंध में पहले ही जांच की जा चुकी है । संस्थान में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं पाया गया ।

बिहार में तटबंध का निर्माण

3058. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा की बाढ़ से बचाव के लिए बिहार में बक्सर से कोयलवार तक 104 किलोमीटर लम्बे तटबन्ध का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) क्या तटबंध का निर्माण-कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है ;

(ग) क्या न तो उक्त प्रयोजन के लिए अधिगृहीत भूमि के लिए अब तक मुआवजा ही दिया गया है और न ही विस्थापितों को अपने मकानों के निर्माण के लिये भूमि आवंटित की गई है ;

(घ) क्या यदि बारिश शुरू होने से पहले तटबंध पूरा नहीं होता है तो न केवल तटबंध के लिए डाली गई मिट्टी ही बह जाएगी, बल्कि इसके परिणामस्वरूप आस पास के ग्रामों के निवासियों को भी भारी क्षति होगी; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार नदी में बाढ़ आने से पूर्व ही तटबंध का निर्माण पूरा करने और ग्रामवासियों को मकान बनाने के लिए स्थान देने और मुआवजा देने का है ;

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (ङ) बिहार सरकार ने 10.10 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर बक्सर से कोइलवार तक एक तटबंध बनाने के लिए एक स्कीम तैयार की है । इस स्कीम में गंगा के दक्षिणी किनारे पर 96 किलोमीटर तक, सोन और गंगा के संगम से कोइलवार तक सोन के पश्चिमी किनारे के साथ 11 किलोमीटर तक, गंगा (पश्चिमी) के दोनों किनारों के साथ 20 किलोमीटर तक और गंगा (पूर्वी) के दोनों किनारों के साथ 38 किलोमीटर तक, तटबंधों का निर्माण परिकल्पित है । इस स्कीम से 79,000 हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलने की आशा है । यह स्कीम योजना आयोग द्वारा मई, 1973 में मंजूर की गई थी और इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है ।

श्रमिकों की मजदूरी में और सामग्री की लागतों में वृद्धि हो जाने के कारण बक्सर-कोइलवार तटबंध स्कीम की अब अनुमानित लागत लगभग 30 करोड़ रुपए आंकी गई है । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि स्कीम की लागत में इस वृद्धि को ध्यान में रखते हुए और पटना बाढ़ सुरक्षा स्कीम के तात्कालिक कार्यों के निर्माण के कारण भी इन दोनों स्कीमों के बीच भी तटबंधों की विभिन्न पहलुओं के निर्माण-कार्यों की प्राथमिकताएं दुबारा निर्धारित करना आवश्यक हो गया है । बक्सर-कोइलवार स्कीम का निर्माण 1973-74 में शुरू किया गया था और यह संभावना थी कि यदि धन उपलब्ध हो जाता है तो यह स्कीम पांच वर्ष में पूरी हो जाएगी । लेकिन धन की तंगी के कारण 1976-77 तक केवल 429 लाख रुपए ही खर्च किए जा सके । 1977-78 के लिए प्रस्तावित परिव्यय 200 लाख रुपए है । अब इस स्कीम का 1980-81 में पूर्ण हो

जाने की संभावना है बशर्ते कि धन उपलब्ध हो जाए। इस प्रकार के इतने बड़े तटबंधों के लिए यह जरूरी है कि इनका निर्माण चरणों में किया जाए और निर्माण के दौरान कार्यों को सुरक्षात्मक तरीकों से करने के लिए उपयुक्त सावधानियां और उपाय किए जाएं।

चूंकि बाढ़ नियंत्रण स्कीमों का आयोजन और कार्यान्वयन राज्य सरकार के कार्य-क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, प्रभावित लोगों को अधिगृहण की गई भूमि का मुआवजा देना तथा घरों के लिए जमीन का आबंटन करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। इस बारे में केन्द्र के पास कोई जानकारी नहीं है।

मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना

3059. **श्री हुकमदेव नारायण यादव :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सारे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए मातृ भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने की सरकार की कोई योजना है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चन्दर) : ऐसी कोई योजना नहीं है। शिक्षा मुख्य रूप से राज्य का विषय है और इस मामले में कार्यवाई करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को है।

Import of Tractors

3060. SHRI P. M. SAYEED: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether the present Government intend to import tractors to meet the demands for the same; and

(b) if so, from which country and their number?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI SURJIT SINGH BARNALA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Supply of electricity for domestic use

3061. SHRI R. K. AMIN: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether there is any proposal to supply electricity for domestic use to the resident of Sultanpuri Resettlement Colony;

(b) if so, the reasons for stoppage of work regarding laying of cables; and

(c) when Government propose to restart the work?

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) Yes, Sir.

(b) The work has not started yet since financial arrangements have not been sorted out.

(c) Does not arise as the work has not started yet.

राजस्थान में चावल मिलरों द्वारा चावल के बारदाने की दर निर्धारित करना

3062. **श्री मीठा लाल पटेल :** क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में चावल मिलर लेवी चावल के मामले में बारदाने की दर प्रति क्विंटल की दर में निर्धारित करते हैं